भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1842

11 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

उत्तर प्रदेश राज्य में उचित मूल्य की दुकानें

1842. श्री राजीव राय:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) और ई-पीओएस समर्थित उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) की संख्या कितनी है;

(ख) क्या मऊ और बलिया जिलों सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में बेकार इंटरनेट संपर्क के कारण उत्पन्न होने वाले व्यवधान से उचित मूल्य की दुकानों पर वास्तविक समय डेटा सत्यापन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या उंगलियों के घिसे-पिटे निशान, बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण (उंगलियों के निशान की पहचान) की चुनौतियों के कारण होने वाली बायोमीट्रिक विफलता का श्रमिकों और वृद्ध लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): उत्तर प्रदेश राज्य में उचित दर की दुकानों (एफपीएस) की कुल संख्या 73138 है और सभी एफपीएस ई-पीओएस से लैस हैं।

(ख): कुछ राज्यों में दूरस्थ स्थानों/अस्पष्ट/नेटवर्क रहित क्षेत्रों में स्थित एफपीएस में ई-पीओएस उपकरणों के लिए इंटरनेट/कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, दूरसंचार विभाग से इंटरनेट/कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं को हल करने का अनुरोध किया गया है। लाभार्थियों को इंटरनेट/कनेक्टिविटी संबंधी किसी भी समस्या का सामना किए बिना, चालू ई-पीओएस डिवाइस वाले किसी भी एफपीएस से अपनी पात्रता का खाद्यान्न लेने का अधिकार दिया गया है। ई-पीओएस डिवाइस सीमित/बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऑफ़लाइन मोड में काम करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ऑफ़लाइन ई-पीओएस डेटा को पीडीएस ऑनलाइन सिस्टम के साथ सिंक्रनाइज़ करने के लिए ई-पीओएस डिवाइस को समय-समय पर नेटवर्क क्षेत्र में आना पड़ता है।

...2/-

(ग) और (घ): इस विभाग को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों से इस पहलू पर कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया या रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग संबंधी समस्याओं, अन्य तकनीकी कारणों या लाभार्थी के बायोमेट्रिक्स के प्रमाणन में विफलता के कारण किसी भी वास्तविक लाभार्थी/परिवार को सब्सिडी वाले खाद्यान्न के पात्र कोटे से वंचित नहीं किया जाएगा।

*****